

अमेरिका के पाकिस्तानी मोह में फंसने की तार्किकता

विचार

“ एक बार फिर मामला है कि आप अमेरिकियों को एक-दो सांप ऐसे सौंप दें कि वे आपकी सपेरागिरी के कायल हो जाएं। यहां तीन कारण हो सकते हैं कि क्यों पश्चिमी देश पाकिस्तान के मोहणाश में फंसने को तैयार हैं : पहला, आतंकियों पर पाकिस्तान का निरंतर प्रभाव उसे एक कीमती मित्र बनाता है। हाल ही में, पाकिस्तान ने मोहम्मद शरीफुल्लाह ‘जफ़र’ सहित इस्लामिक स्टेट के पांच लड़ाके अमेरिकियों को सौंपे, जो 2021 में काबुल हवाई अड्डे के पास बम हमले में शामिल थे, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। तथ्य तो यह कि भले ही ‘जफ़र’ इस काबुल हमले का मास्टरमाइंड रहा हो, लेकिन वह आईएस के शीर्ष नेतृत्व में नहीं था। उसे सौंपकर मुनीर अपने लिए समय और प्रभाव खरीद रहे हैं- पाक की अमेरिका को लेकर रणनीति का अभिन्न अंग।

ज्यात मल्हत्रा

ऑपरेशन सिंधुर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ़ भारत द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई के औचित्य को समझाने के बासे पिछले दो हफ्तों में 40 से ज्यादा भारतीय याजनेताओं और पूर्व राजनयिकों से बने सात प्रतिनिधिमंडल 33 देशों में भेजे गए, लेकिन गत 14 जून को वार्षिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित पेरेड में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख और अब फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया गया। इस बार की पेरेड में कुछ पुराना फौजी साजो-सामान 1991 के बाद पहली बार दिखा- 6,600 सैनिक, 28 अब्राम टैंक, 28 ब्रैडली लड़ाकू वाहन, 28 स्ट्राइकर वाहन, चार पैलाडिन सेल्फ-प्रोपल्ट हॉविंत्जर तोपें, आठ मार्चिंग बैंड, 24 घोड़े, दो खच्चर और एक कुत्ता ज्ञ कुछ रकेट लॉन्चर और प्रिसिजन-गाइडेड मिसाइलें भी। इस रोज़ डोनाल्ड ट्रंप का 79वां जन्मदिन थी था। इस बीच, सांसदों के सभी सातों प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौट आए और उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। लंदन, पेरिस, रोम, कोपेनहेगन, बर्लिन और ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के मुख्यालय की यात्रा पर गए भाजपा के रविंशंकर प्रसाद ने लौटने पर संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने इन सभी यूरोपीय शहरों में अपने वार्ताकारों को आतंकवाद के प्रति भारत की 'जीरो टॉलरेंस' बोरे बताया। प्रसाद ने कहा : 'हमने साफ़ कर दिया कि हम पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ़ नहीं। समस्या पाकिस्तान के जनरलों से है, जिनसे खुद वहाँ के लोग भी तंग आ चुके हैं।' लगता है प्रसाद खबरों को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। दो दिन पहले ही वार्षिंगटन डीसी में, यूएस सेंट्रल कमांड के शक्तिशाली कमांडर जनरल माइकल ई कुरिल्स्न ने यूएस सीनेट सशक्त सेवाएं समिति को बताया कि पाकिस्तान एक 'खास साझेदार' है, खासकर आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर। कुरिल्स्न ने आगे कहा, 'मुझे नहीं लगता कि यह कोई बाइनरी स्विच जैसा होना चाहिए कि यदि हम भारत के साथ संबंध रखें, तब हमें पाकिस्तान के साथ (संबंध) नहीं खेलने चाहिए।' इसमें कुछ दिन



हफले, कुरिक्का के बॉस, डोनॉल्ड ट्रम्प ने भी घोषणा की थी, ‘पाकिस्तान के पास बहुत मजबूत नेतृत्व है। कुछ लोगों को यह नागवार लगता है जब वै मैं ऐसा कहता हूँ, लेकिन हुआ यही है, और उन्होंने उस युद्ध को रोक दिया। मुझे उन पर बहुत गर्व है। क्या मुझे श्रेय मिल रहा है? नहीं। वे मुझे किसी भी चीज़ का श्रेय नहीं दे रहे। तब भारत और अमेरिका के बीच प्रसिद्ध ‘रणनीतिक साझेदारी’ का क्या बना? इसके अलावा, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हमें सख्त नापसंद ‘हाइफनेशन’ (दोनों को बराबर पलटे में तोलना) फिर से बन गया है? बड़ा सवाल, बेशक, यह कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अभी भी ऐसे मुल्क के मोहापाश में क्यों फंसा है, जिसकी अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है (आईएमएफ से 25 क्रूज़ ले रखे हैं), जो कहने भर का लोकतंत्र है और भारत में आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड बना हुआ है, जिसमें नवीनतम कांड पहलगाम में हुआ दुर्दांत हमला है। निश्चित रूप से, काली दाल में फिर कड़छी चल रही है। कम-से-कम 2008 के बाद से, जब भारत और अमेरिका ने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जहां अमेरिकी भारत के साथ साझेदारी के लिए उत्सुक रहे वहीं ऐसे ही भारतीय भी। यह सिर्फ इस बारे नहीं था कि भाग्त बित्तने बोंबंग विमान

खरीदेगा, हालांकि इससे रिश्तों में मदद मिल सकती थी। अमेरिका ने व्यापारिक आदान-प्रदान पर टिकी साझेदारी से परे वास्तविक संबंध की मिम को पहचाना, जिसमें भारत को चीन के प्रति-संतुलन के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन ट्रम्प ने आपसी व्यापार में लेन-देन में बराबरी रखने की अपनी प्रवृत्ति के साथ दुनिया में उलटफेर कर दिया। पाकिस्तान को एक नयी राह की तरह देखा जाने लगा है। इहिलेरी किलंटन ने 2012 में पाकिस्तान को लेकर दुविधा को बहुत भावुकता से व्यक्त किया था ‘बात यह नहीं कि आपने पिछवाड़े में कितने सांप पाल रखे हैं, और क्या वे आपको नहीं ढंस सकते’। एक बार फिर मामला है कि आप अमेरिकियों को एक-दो सांप ऐसे सौंप दें कि वे आपकी सपेरिगिरी के कायल हों जाएं। यहां तीन कारण हो सकते हैं कि क्यों पश्चिमी देश पाकिस्तान के मोहपाश में फंसने को तैयार हैं: पहला, आंतिकियों पर पाकिस्तान का निरंतर प्रभाव उसे एक कीमती मित्र बनाता है। हाल ही में, पाकिस्तान ने मोहम्मद शरीफुल्लाह ‘जफर’ सहित इस्लामिक स्टेट के पांच लड़ाके अमेरिकियों को सौंपे, जो 2021 में काबुल हवाई अड्डे के पास बम हमले में शामिल थे, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक मरे गए थे। तथ्य ही यह कि भले ही ‘जफर’ इस काबुल हमले

मास्टररामाइंड रहा हो, लेकिन वह आईएस के पैरेंज नेतृत्व में नहीं था। उसे सौंपकर मुनीर अपने नए समय और प्रभाव खीरद रहे हैं - पाक की अमेरिका को लेकर रणनीति का अधिकार अंग, जो दशकों कारगर रहा। कुरिल्ला द्वारा पाकिस्तानी प्रशंसा के तुरंत बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा रिखिद की दो प्रमुख समितियों में पाकिस्तान को उद्धम ओहदों पर को नामित किया गया-लिलावान पर प्रतिवंध समिति की अध्यक्षता और भारतकावाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष। जब अमेरिका को अहसास हो गया है कि पाकिस्तानी द्वारा प्रतिष्ठान की उपयोगिता भले कामों में उत्तरवाची की अपेक्षा तुकसान पहुँचाने वालों से बढ़तने में कहीं अधिक है, तो वर्ती न राक्षस को छु-छु छिनवाला डालते रहें ताकि वह काबू रहे? दूसरा, जब कोई ट्रंप को ना कह दे या बतात करें, तो यह उनके बेहद अंहकारी स्वभाव को रास नहीं आता। इसलिए जब उन्होंने और उनके सहयोगियों ने 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के लिए 'पद्धत्यस्थाप्ता' करने की घोषणा की, तब भारत यह बात नकरारी दी ट्रंप यह बात 12 बार और (हरहा चुके हैं)। हकीकत यह कि भारतीय वायु नाना ने 10 मई को 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला करके करारा संदेश दिया, जिसने पाकिस्तानियों और अमेरिकियों दोनों

‘इश्वराय भय’ पदा कर दिया, आर संघष द खत्म हो गया। ट्रॅप जो भी कहें, उसे अपने की जहमत क्यों उठाएं? तीसरा, पाकिस्तान खुद को पीड़ित दिखाने में माहिर है, कोई छोटी विडंबना नहीं। भारत को धौनीनी देने वाले अभियान को आगे बढ़ाकर किस तरिके संधि नदी के पानी को रोक 23 करोड़ को प्यासा मारना चाहता है’), वह वैश्विक नुभूति पाने की कोशिश में है। ऑफरेशन र के बाद वाशिंगटन व लंदन में बिलावल की मुहिम का उद्देश्य यही था। आतंकी में पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान की भूमिका सवालों को इस प्रश्न से दर्खिनार कर दिया गया है कि ‘सबूत कहाँ है?’ पाकिस्तान आतंकवाद के साथ अपने अनुभवों की तुलना ई आतंकी हमले में अजमल कसाब जैसा सबूत पाने से करना चाहता है, जिसमें भग 170 लोग मरे गए थे। अमेरिका की नुभूति दिख रही है। जनरल कुरिल्स ने कहा 2024 में पाकिस्तान को करीब 1,000 आतंकी हमले सहने पड़े, जिसमें 700 ताकर्मी मरे गए और 2,500 घायल हुए। लल है कि अब आगे क्या। जनरल मुनीर ने असिकियों को शीशे में उत्तर लिया है, लिहाजा असिकि सेना की परेड में उनकी उपस्थिति, कुछ मांगें और करने का मौका देगी।

5-अमेरिका व्यापार में शून्य-टैरिफ का रोध किया जाएगा; इससे भी महत्वपूर्ण है यह मुद्दाव दिया जाएगा कि अमेरिका भारत संधि जल संधि बहाल करने और वार्ता फिर बहुरक्षण को दबाव डाले। ग्रीष्मऋतु आगे और कठिन होने वाली है। हो सकता है कि उत्तर के पास कुछ पते हों, लेकिन उसे यह बना होगा कि उन्हें सीने से लगाकर न रखे। पाकिस्तान की बेर्इमारी बारे अपना आकलन करें, लेकिन इस बात पर धमंडन करें कि बड़ा और बेहतर दक्षिण पश्चिमाई राष्ट्र है। न तर होगा कि अपने अंदर ज्ञाकें और अपने वक्य या फिर सन ल्जु को फिर पढ़ें। जिनके बिक अपने दोस्तों को हमेशा करीब रखना छा विचार है, लेकिन दुश्मनों को और भी दीक रखें।

खेका ‘द टिक्कन’ की पथ्यान संपादक हैं

— — — — —

संपादकीय

दिल्ली में स्कूल फीस पर कानून का शिकंजा

दिल्ली के निजी विद्यालयों में मनमाने तरीके से शुल्क बढ़ाए जाने पर सबाल उठते रहे हैं। अभी हाल ही में द्वारका में कई अधिभावकों ने सरकार की अनुमति के बिना एक विद्यालय पर शुल्क बढ़ातेरी का आरोप लगाया था। साथ ही दावा किया था कि बच्चों और उनके माता-पिता पर दबाव बनाने के लिए कुछ स्कूलों में अतिरिक्त कर्मी तैनात किए जाते हैं। निजी विद्यालयों की निरंकुशता का मुद्दा अदालतों में भी उठता रहा है ऐसा भी नहीं कि शिक्षा निदेशालय को वस्तुस्थिति मालूम न हो। सबाल यह है कि निजी विद्यालयों को मनमानी करने को छूट किसने दी? कौन लोग हैं जो इहें अब तक शह देते रहे हैं? लगातार शिकायतें मिलने पर दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा (पारदर्शिता निर्धारण और शुल्क विनियमन-2025) विधेयक पारित करने का निर्णय किया था, मगर किन्हीं कारणों से यह पेश नहीं किया जा सका था। सरकार निजी विद्यालयों को अब जवाबदेह बनाना चाहती है अब इस विधेयक को अध्यादेश के जरिए लागू करने का दिल्ली मंत्रिमंडल का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे शुल्क प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और अधिभावकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। निजी विद्यालयों को अब जवाबदेह बनाना होगा। वे अधिभावकों पर मनमाने तरीके से आर्थिक बोझ नहीं डाल सकेंगे। अब दिल्ली के निजी स्कूल नहीं वसुल पाएंगे मनमानी फॉर्म, पेरेंट्स को मिलेगा लाभ; रेखा गुप्ता सरकार ने लिया बड़ा फैसला हैरत की बात तो यह है कि निजी विद्यालयों में शिक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य मदों में राशि जोड़कर कई वर्षों से वसुली की जाती रही है। विकास शुल्क के नाम पर अधिभावकों पर दबाव बनाया जाता है। मगर, अब इस पर रोक लग सकेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना शुल्क बढ़ाने पर निजी विद्यालयों और दिल्ली शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी किए थे। इसमें दोशय नहीं कि बार-बार शुल्क बढ़ाए जाने से गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों पर नाहक ही आर्थिक बोझ पड़ता है। नवा अध्यादेश लागू होने के बाद निजी विद्यालय निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क नहीं वसुल सकेंगे। इस अध्यादेश में ऐसे कई प्रावधान हैं, जिनसे अधिभावकों को चिंता से मुक्ति मिलेगी। शुल्क के नाम पर विद्यार्थियों को पेरेशान किए जाने पर पचास हजार के जुमाने का प्रावधान निःसंदेह सरकार का सख्त कदम है।



धर बनान म बास साल लग गए। अब मर्स यह तीन कमरों का घर हाल ही में बनकर तैयार हुआ था। जब भूकंप में मेरा घर गिरा उस समय मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, लेकिन मैंने हालात का सामना करने की हिम्मत रखी। मैंने सालों मेहनत की और आखिरकार नया घर बना लिया, लेकिन अब नया घर बनान मेरे बस की बात नहीं है। छोटी-मोटी कथामोड़ ऐसी ही होती है। नियंत्रण रेखा पर गोलाबार्स मूल रूप से पहलगाम में आतंकी घटना के बाद शुरू हुई थी, लेकिन सात मई से दस मई तक इसकी तीव्रता असाधारण रही। सबसे ज़्यादा तबाही इन्हीं चार दिनों में हुई। इस स्थिति के दौरान सीमा के नज़दीक रहने वाले गैरकर्त्ता परिवार प्रलय में फ़ूँक लगा

य लाग मालावारा क दरान अपन घे, खत
और यहां तक कि जानवर भी छोड़कर भाग
गए थे। बारामूला के ऊरी इलाके में भी इसी
तरह का पलायन एक परिवार के लिए आफत
लेकर आया। यह परिवार अपनी कार से
सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहा था, तभी
घर से कुछ किलोमीटर दूर सीमा पार से दागा
गया गोला उनकी कार से टकराया, जिसमें
गुहणी नरगिस बानो की मौत हो गई और
परिवार के दो सदस्य धायल हो गए। अब
ज्यादातर लोग लौट आए हैं, लेकिन उनके
सामने कई परेशानियां हैं। शायद उनकी
सबसे बड़ी समस्या मोर्टार के गोले हैं, जो
बिना फेटे रह गए हैं। हालांकि सेना ने बड़े
अधिकार के तहत इनमें से ज्यादातर गोले

केरल के सम्पूर्ण डिजिटल साक्षरता मॉडल को पूरे भारत में अपनाने की जरूरत

प्रो. मिलिंद कुमार शर्मा

A photograph showing a group of approximately 15-20 people at what appears to be a political or public event. In the center, a man wearing a white short-sleeved shirt and white dhoti pants is seated on a wooden stool, looking down at a black smartphone he is holding in his hands. To his right, a woman in a yellow and white sari is gesturing with her right hand towards the camera. Several other individuals are visible in the background, some holding small red and white flags or banners. The setting is outdoors at night, with artificial lighting illuminating the scene.

स्वरूप दे दिया। स्थानीय निकायों और स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस प्रयास में उत्तसाहपूर्वक भाग लिया। अब प्रश्न यह है कि इस मॉडल को पुरे भारत में कैसे लागू किया जा सकता है। भारत जैसे विविधता प्रधान देश में किसी एक मॉडल को सीधे लागू करना न तो संभव होगा न ही उचित होगा। अतः सर्वप्रथम प्रत्येक राज्य को अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस मॉडल को ढालना होगा। कुछ राज्यों में ऐगोलिक बाधाएं हैं तो कुछ में सामाजिक-पारिवारिक रूढियां। इन सभी विद्यान में रखकर डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमों को तैयार करना होगा। ग्रामीण भारत में इंटरनेट की पहुंच अभी सीमित है, इसलिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अंत सशक्त करना आवश्यक है। भारतनेट जैसे योजनाओं को तेज गति से क्रियान्वित करना होगा। जिससे हर पंचायत स्तर पर ब्रॉडबैंड सुविधा सरलता से उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक रूप से विद्यालयों की स्थापना की जिले और ब्लॉक में स्थानीय डिजिटल प्रशिक्षण

कद्रां का स्थापना का जाना चाहिए। डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके उन्हें अपने समुदायों में प्रशिक्षण कार्य में लगाया जा सकता है। इससे समाज में डिजिटल जागरूकता का चातावरण बनेगा और तकनीक का समावेश तेजी से होगा। शिक्षण संस्थानों की सक्रिय भागीदारी इस अभियान में क्रांतिकारी सिद्ध हो सकती है। स्थानीय तकनीकी संस्थान अपने विधायियों को समय समय पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इससे युवा विद्या?थर्यों को अपने सामाजिक दायित्व निवर्णन का भी भान हो सकेगा। सरकार को निजी संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत इस अभियान को सफल करने के लिए नित नवाचार करने के प्रबल प्रयास करने होंगे। निजी क्षेत्र तकनीकी कौशल, ज्ञान, सामग्री और संसाधनों के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके अतिरिक्त, यह निर्तात आवश्यक कि है डिजिटल साक्षरता की सामग्री व संसाधन स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हो, जिससे आम नागरिक उसे सहजता से उसे समझ व प्रयोग कर सकें। इन प्रयासों के मध्य यह भी आवश्यक है कि कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन की

यवस्था बनाइ जाए। यदि किसी राज्य में नना अपेक्षाकृत धीरी गति से आगे बढ़ रही है तो वह अपय रहते सुधारात्मक कदम उठाने के लिए करने होंगे। यही नहीं, लोगों की सामाजिक कला में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जिससे वे तकनीक को सुगमता से स्वीकार कर सकते हैं। अन्य प्रयास में कुछ चुनौतियाँ अवश्य होंगी। अन्य संसाधनों की कमी से जूझ सकते हैं, तब तकनीकी प्रशिक्षकों की उपलब्धता एक हो सकती है। अनेक समुदायों में बुजुर्गों द्विवादी सोच के चलते तकनीक अपनाने की जानी हो सकती है। परन्तु सरकार, समाज, और अन्य हितधारक इस क्षेत्र में मिलकर बद्ध तरीके से कार्य करें, तो यह कार्य व भी नहीं है। अंततः कहा जा सकता है कि ल का डिजिटल साक्षरता मॉडल भारत के एक आदर्श उदाहरण है। यह न केवल की दृष्टि से अपितु सामाजिक समावेशन के भी अन्यत प्रभावशाली व लाभकारी है। इसके 'डिजिटल इंडिया' स्वन को मूर्त रूप तो अन्य राज्यों को केरल से सीख लेकर, अ आवश्यकताओं के अनुसार योजना ओं लकर, और समाज के प्रत्येक वर्ग की दृष्टि से डिजिटल साक्षरता के इस आंदोलन देश में प्रचार प्रसार करना होगा। तभी भारत शक्ति और समावेशी डिजिटल राष्ट्र के रूप बढ़ सकेगा।

